

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उतरांचल, उतराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण बुधवार 28 अक्टूबर 2026 वर्ष-9,अंक-267 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com



www.facebook.com/krantisamay1



www.twitter.com/krantisamay1

## सीईसी के इस्तीफे तक नहीं रुकेगा विपक्ष

दिल्ली में राहुल गांधी का दावा, की जन सुनवाई राहुल गांधी ने कहा-ऊपर से ही हो रही वोट चोरी

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मंगलवार को दिल्ली के त्रिलोकपुरी स्थित ब्लॉक 20 में वोट अधिकार जीने का अधिकार जन सुनवाई में शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर हमला तेज करते हुए आरोप लगाया कि देश में ऊपर के स्तर से वोट चोरी की जा रही है और गरीबों के नाम जानबूझकर मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष एकजुट है और जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें पद से नहीं हटाते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। राहुल गांधी ने कहा, इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष एकजुट है। वोट भारत के हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। इसके बावजूद देशभर में करोड़ों लोगों से उनका यह अधिकार यानी वोट व्यवस्थित तरीके से छीना जा रहा है।



**ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक आंदोलन जारी रखने की बात**

राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि जब विपक्ष उनसे सवाल करता है, तो उन्हें जवाब नहीं मिलता। उन्होंने कहा, जब हम ज्ञानेश कुमार से सवाल करते हैं, तो वह जवाब नहीं देते। विपक्ष तब तक नहीं रुकेगा, जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं दे देते। राहुल गांधी के ये बयान मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्ष के जारी विरोध के बीच आए हैं। इंडिया ब्लॉक के दल मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं और नाम हटाए जाने के मुद्दे पर चुनाव आयोग से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं।

**गरीबों के नाम जानबूझकर**

**हटानेका आरोप**

कांग्रेस सांसद ने आगे कहा, हम लंबे समय से यह मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन अब पूरा देश समझने लगा है कि ऊपर के स्तर से वोट चोरी हो रही है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि गरीबों के नाम मतदाता सूची से जानबूझकर हटाए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इससे उनके अधिकार और सुविधाएं भी प्रभावित हो रही हैं। राहुल गांधी ने कहा, गरीबों के नाम जानबूझकर मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं और उनके अधिकार तथा सुविधाएं छीनी जा रही हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है। एक ऐसा ‘नया हिंदुस्तान’ बनाने के लिए, जो कुछ चुने हुए अरबपतियों का हो। जहां आम नागरिकों और गरीबों के अधिकार न हों और देश केवल अरबपतियों के हित में चलाया जाए। राहुल गांधी ने कहा कि इस जन सुनवाई के जरिए लोगों ने बताया कि चार बूथों से 416 नाम कथित तौर पर अवैध तरीके से हटाए गए हैं। उन्होंने कहा, भारत के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है। हम लंबे समय से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। आज लोगों को समझ आ गया है कि वोट चोरी हो रही है और गरीबों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं।

## डेटा प्रोटेक्शन कानून से खबरों की रिपोर्टिंग करना होगा मुश्किल

21 मीडिया ग्रुप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट और इससे जुड़े नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा। यह याचिका डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन ने दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि कानून में पत्रकारिता को छूट नहीं मिलने से खोजी पत्रकारिता, खबरों की रिपोर्टिंग और गोपनीय स्रोतों की पहचान सुरक्षित रखने में मुश्किल हो सकती है।



**डेटा कानून को चुनौती देने वालों में अंबानी-अडानी की भी कंपनियां**

डेटा प्रोटेक्शन कानून और उससे जुड़े नियमों के कई प्रावधानों को चुनौती दी गई है। एसोसिएशन में देश के 21 न्यूज पब्लिशर्स शामिल हैं। इनमें मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाला नेटवर्क 18, गौतम अडानी का चैनल, इंडियन एक्सप्रेस जैसे मीडिया समूह शामिल हैं। केंद्र सरकार ने डिजिटल माध्यमों पर लोगों की निजी जानकारी की सुरक्षा के लिए यह कानून बनाया है।

संक्षिप्त

समाचार

### राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित होगी

### चंडीगढ़ पुलिस

**बड़ी उपलब्धि, 1 नवंबर को**

**अमित शाह सौंपेंगे सम्मान**

**चंडीगढ़ (एजेंसी)।** सिटी ब्यूटीफुल की चंडीगढ़ पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि सामने आई है। पुलिस बल को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करने के प्रस्ताव को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 26 अक्टूबर को इसकी जानकारी दी। केंद्रीय गृह



मंत्री अमित शाह 1 नवंबर को चंडीगढ़ पुलिस को यह सम्मान प्रदान करेंगे। बता दें कि राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुलिस संगठनों को दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। यह सम्मान कानून-व्यवस्था बनाए रखने, पुलिस के आधुनिकीकरण, आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई और नागरिकों को बेहतर सेवाएं देने में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। रिकॉर्ड के मुताबिक, वर्ष 2009 से अब तक चंडीगढ़ पुलिस ने कानून-व्यवस्था से जुड़े 60,501 कार्यक्रमों और आयोजनों को संभाला है। इनमें वर्ष 2025 के 2,582 कार्यक्रम भी शामिल हैं।

### वेस्ट बंगाल में रेप-मर्डर के आरोपी की मुठभेड़ में मौत

### क्राइम सीन रीक्रिएशन के दौरान रिवॉल्वर छीनी थी

**कोलकाता (एजेंसी)।** पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के गाथघाटा में 17 साल की छात्रा से रेप और हत्या के आरोपी 23 साल के युवक की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई। सोमवार रात क्राइम सीन रीक्रिएशन के दौरान आरोपी ने पुलिसकर्मी की सर्विस रिवॉल्वर छीनकर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी। पश्चिम बंगाल में 1 मई से 24 सितंबर तक रेप के 2,454 मामले



दर्ज हुए। यानी इन पांच महीनों में हर दिन औसतन करीब 17 रेप के मामले सामने आए। क्राइम सीन रीक्रिएशन के दौरान पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर फायरिंग करने वाले आरोपी की मौत की यह तीन महीने में दूसरी घटना है। पुलिस के मुताबिक, गोली लगने के बाद आरोपी को चांदपाड़ा ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस अधिकार के मुताबिक, आरोपी ने रिवॉल्वर कैसे छीनी और फायरिंग तक घटनाक्रम कैसे पहुंचा, इसकी जांच की जा सकती है। फायरिंग के दौरान पुलिसकर्मीयों ने पास की नहर में छिपकर बचाव किया।

## पैसे देकर चलाया गया था ई 20 के खिलाफ अभियान

**केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया दावा**

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** इथेनॉल मिक्स पेट्रोल यानी ई 20 पर हाल में खासकर सोशल मीडिया पर काफी बवाल मचा था। कई लोगों ने शिकायत की थी इससे गाड़ियों का इंजन खराब हो रहा है और माइलेज पर भी असर पड़ रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पेट्रोल में 20 फीसदी इथेनॉल मिलाने को लेकर विरोध ‘पैसे देकर चलाया गया अभियान’ था। गडकरी ने एक कार्यक्रम में कहा, “तीन महीने पहले ई20 ईंधन के खिलाफ काफी शोर मचाया गया था। अब ई20 ईंधन को लेकर नाराजगी खत्म हो गई है... यह पैसे देकर चलाया गया अभियान था।



## तमिलनाडु की जेल से 17 कैदी फरार, 5 गिरफ्तार

मिर्गी के दौरे का नाटक कर गाड़ी पर हमला किया

1995 के बाद प्रदेश की यह दूसरी बड़ी घटना

**चेन्नई (एजेंसी)।** तमिलनाडु के थेनी जिले की थेक्कमपट्टी सब-जेल से सोमवार देर रात 17 कैदी फरार हो गए। कैदियों ने एक साथी को मिर्गी का दौरा पड़ने का नाटक किया। उसकी मदद के लिए जैसे ही जेलकर्मी सेल में पहुंचे, सभी ने उन पर हमला कर दिया और फरार हो गए। पुलिस ने अब तक 5 कैदियों को गिरफ्तार किया है। बाकी कैदियों की तलाश जारी है। उन्हें पकड़ने के लिए 17 स्पेशल टीमें भेजी गई हैं। आसपास के जिलों में अलर्ट जारी किया गया है और पड़ोसी राज्य केरल की पुलिस को भी सूचना दी गई है। घटना के बाद ड्यूटी पर तैनात 9



जेलकर्मियों और अधिकारियों को लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। तमिलनाडु में कैदियों के एक साथ फरार होने को यह 1995 के बाद बड़ी घटनाओं में से एक है।

उस साल वेल्लोर किले के अंदर बने विशेष हिरासत केंद्र से एसएफआई के 43 सदिग्ध सुरंग बनाकर फरार हो गए थे। उस सुरंग की लंबाई करीब 153 फीट (47 मीटर) थी।

### 16 जगहों पर चेकपोस्ट

**वाहनों की जांच जारी**

घटना के बाद आसपास के जिलों की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। पड़ोसी डिंडीगुल जिले में 16 जगहों पर चेकपोस्ट बनाए गए हैं। यहां से गुजरने वाले वाहनों की जांच की जा रही है, ताकि फरार कैदियों को पकड़ा जा सके। डिंडीगुल के पुलिस अधीक्षक एस. जयकुमार ने चेकपोस्ट बनाए जाने की पुष्टि की है। पुलिस ने मद्रै, डिंडीगुल और केरल के इडुक्की जिले के अधिकारियों को भी घटना की जानकारी दी है।

# विशाखापट्टनम से टकराने वाला है तूफान ‘अर्नब’

**ओडिशा-आंध्र में स्कूल बंद, बंगाल में भी बारिश का अलर्ट**

**भुवनेश्वर (एजेंसी)।** बंगाल की खाड़ी में उठे भीषण चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ के पूर्वी तट की ओर बढ़ने के साथ ओडिशा के कुछ हिस्सों में मंगलवार को तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने तूफान के 28 अक्टूबर की सुबह आंध्र प्रदेश के तट पर बापटला और विशाखापत्तनम के बीच यानम के पास पहुंचने का अनुमान जताया है। आईएमडी के अनुसार, तूफान मंगलवार सुबह बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य हिस्से में विशाखापत्तनम से लगभग 260 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में केंद्रित था। इसके मंगलवार शाम तक पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ने और उसके बाद उत्तर-पश्चिम की ओर मुड़ने की संभावना है। तूफान के तट से टकराने के दौरान 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और पवन के झोंकों की गति 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का



अनुमान है। ओडिशा में आईएमडी ने पुरी, गजपति, गंजाम, रायगढ़ा, कोरापुट और मलकानगिरि जिलों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में 12 से 20 सेंटीमीटर तक बारिश

हो सकती है। बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, कटक और खुर्दी सहित 16 जिलों के लिए सात से 11 सेंटीमीटर बारिश का अनुमान जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

**बंगाल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान**

भीषण चक्रवाती तूफान अर्नब के प्रभाव से पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में 28 से 30 अक्टूबर के बीच भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य हिस्से में स्थित इस तूफान के उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ने और 28 अक्टूबर की सुबह आंध्र प्रदेश के तटीय हिस्से पर पहुंचने की संभावना है। दक्षिण बंगाल में 28 और 29 अक्टूबर को दक्षिण 24 परगना, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, पुरलिया, बांकुड़ा और पश्चिम बर्धमान जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान है। आईएमडी ने कहा कि कोलकाता में अगले 48 घंटे के दौरान हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

### अरुणाचल पर कछे के फर्जी वीडियो पर भड़की बीजेपी

**किरण रिजिजू ने कांग्रेस को घेरा**

**कहा-देश से माफी मांगे**

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** सोशल मीडिया पर भारत-चीन सीमा को लेकर एक वीडियो सामने आया, जिसमें दावा किया गया कि चीनी वाहन भारतीय क्षेत्र में घुस आए हैं। एक दूसरे वीडियो में सेना के वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा गया कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया है और भारतीय सैनिकों को जरूरी सामान तक नहीं मिल रहा। इन दावों ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए, लेकिन भारतीय सेना की जांच में दोनों वीडियो भ्रामक पाए गए।



## यूपी में गरीबों को 100 चूजे मुफ्त में देगी सरकार

**गाय खरीदने पर 50 हजार सब्सिडी का भी किया ऐलान**

**टीचिंग स्टाफ को 5 लाख का फ्री इलाज, लिए 22 फैसले**

**लखनऊ (एजेंसी)।** योगी कैबिनेट ने फैसला किया है कि गाय खरीदने पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी राज्य सरकार देगी। यह फैसला दो गाय खरीदने पर मिलेगी। इसके अलावा गरीब परिवारों को मुर्गी पालन के लिए 100-100 चूजे मुफ्त बांटे जाएंगे। सीएम योगी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने पंचायत चुनाव में वोटर बनने के लिए भी नए प्राविधान को मंजूरी दी।



**पंचायत चुनाव में वोटर बनने के लिए छह महीने का निवास अनिवार्य**

पंचायती राज चुनाव के लिए मतदाता का 6 महीने पहले से उस गांव का निवासी होना अनिवार्य होगा। कैबिनेट ने इसके लिए एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब तक एक्ट में मतदाता को न होना था। अब संशोधन कर तय किया है कि भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची की तरह पंचायत राज की मतदाता सूची में 18 वर्ष की आयु का व्यक्ति जो सामान्य तौर पर 6 महीने या इससे ज्यादा समय से गांव में निवास करता हो उसे मतदाता बनाया जा सकेगा।

**चार सरकारी अस्पताल पीपीपी मॉडल पर चलेंगे**

सरकार ने बरेली के 300 बेड, बांदा के 200 बेड, अंबेडकरनगर के टांडा के 200 बेड और चित्रकूट के कवी के 200 बेड वाले अस्पतालों को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर संचालित करने की मंजूरी दी है। यहां 12 विशेषज्ञ और तीन सुपर-स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की सेवाएं उपलब्ध कराने की योजना है। इलाज और ओपीडी की दरें लखनऊ के अनुरूप रहेंगी। इन अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से भी इलाज कराया जा सकेगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली को मंजूरी दे दी है। इनलैंड वाटर अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। जल परिवहन की देखरेख के लिए अथॉरिटी बनेगी, जिसके अध्यक्ष परिवहन मंत्री होंगे। उन्होंने बताया कि गंगा, यमुना, सरयू, घाघरा समेत प्रदेश की 11 नदियों में चलने वाले नावों और स्टीमर का पंजीकरण अनिवार्य होगा। गैर-यात्री नावों के लिए 50 रुपए शुल्क तय किया गया है। साथ ही दुर्घटना से बचाव और सुरक्षा के लिए यात्रियों के साथ-साथ नाविकों का भी बीमा कराया जाएगा।

# खाली कक्षाएं, फर्जी हाजिरी और अत्वल नतीजे

(लेखक– डॉ. रविशंकर कुमार चौधरी )

बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर समय-समय पर अच्छे परीक्षा परिणामों, विद्यार्थियों की उपलब्धियों और सरकारी योजनाओं की चर्चा होती है। सरकार इन उपलब्धियों को शिक्षा में सुधार का प्रमाण बताती है। लेकिन इस चमकदार तस्वीर के पीछे कुछ ऐसे सवाल भी हैं, जिनसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। क्या विद्यालयों और महाविद्यालयों में नियमित कक्षाएं चल रही हैं? क्या विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है? क्या शिक्षकों की उपस्थिति और पढ़ाई की वास्तविक स्थिति में कोई संबंध है? और क्या परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना वास्तव में ज्ञान और समझ का प्रमाण है?

इन सवालों के बीच खाली कक्षाओं, उपस्थिति के आंकड़ों में संभावित गड़बड़ियों और शिक्षण की कमजोर होती गुणवत्ता पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। शिक्षा केवल नामांकन, उपस्थिति और परीक्षा परिणामों का सरकारी आंकड़ा नहीं है। उसका वास्तविक उद्देश्य विद्यार्थियों में ज्ञान, विवेक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, रचनात्मकता और सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करना है। यदि यह उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा, तो अच्छे परिणामों के बावजूद शिक्षा व्यवस्था की सफलता पर सवाल उठेंगे।

बिहार में शिक्षा के विस्तार के लिए पिछले वर्षों में कई योजनाएं शुरू की गई हैं। विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं बढ़ाने, शिक्षकों की नियुक्ति करने, छात्रवृत्ति देने और विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के प्रयास हुए हैं। इन पहलों का महत्व है, लेकिन इनकी सफलता का आकलन केवल बजट खर्च, नियुक्तियों और परीक्षा परिणामों से नहीं किया जा सकता। यह देखना भी जरूरी है कि कक्षा में वास्तव में क्या हो रहा है और विद्यार्थी कितना सीख रहे हैं।

उपस्थिति का हिसाब रखना प्रशासनिक जरूरत है, लेकिन उपस्थिति को ही शिक्षा मान लेना बड़ी भूल है। किसी विद्यालय में शिक्षक की हाजिरी नियमित हो, विद्यार्थी भी नामांकित हों, फिर भी यदि कक्षा में पढ़ाई नहीं हो रही, तो व्यवस्था अपने मूल उद्देश्य से भटक रही है। इसी तरह, कमाजों पर उपस्थिति पूरी दिखने और वास्तविक स्थिति में अंतर होने की शिकायतें सामने आती हैं, तो उनकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। हालांकि, किसी शिकायत को जांच के बिना पूरे शिक्षक समुदाय पर आरोप बनाने का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए।

### संपादकीय

## पराली की तपिश

यह विडंबना ही है कि जब देश की राजधानी में प्रदूषण की गंभीरता दिखायी देती है तो देश के नीति-निर्माता पराली निस्तारण को लेकर बड़ी-बड़ी बातें करने लगते हैं। अभी कोई अंतिम वैज्ञानिक अध्ययन भी सामने नहीं आया है कि पंजाब या अन्य राज्यों में पराली जलाने की प्रदूषण में कितनी फीसदी भूमिका है। लेकिन एक बात तो तय है कि पराली निस्तारण के जो भी विकल्प दिए जाते हैं, वे समय के अनुरूप किसान की सुविधा व आर्थिकी के अनुरूप नहीं हैं। यदि ये उपाय कारगर होते तो पराली प्रबंधन पर खर्च किए जाने वाले हजारों करोड़ रूपयों पर एक छेटी-सी माचिस भारी न पड़ती। किसान अपने खेतों में पराली को बार-बार यदि आग के हवाले करते हैं तो उसके पीछे का कड़वा सच यह भी है कि धान के अवशेषों को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करने की तुलना में, पराली जला देना उसे सुविधाजनक, सस्ता तात्कालिक निस्तारण का विकल्प नजर आता है। निस्संदेह, जब तक आर्थिक रूप से लाभप्रद विकल्प किसान को नहीं दिया जाता, तब तक केवल सख्खिडी देने या दंडात्मक कार्रवाई करने के बहुत सीमित परिणाम ही सामने आएंगे। सूत्रों के अनुसार पंजाब में 15 सितंबर से 24 अक्तूबर के बीच खेतों में पराली जलाने की 574 घटनाएं दर्ज की गई हैं। यदि पिछले साल के आंकड़ों से इसकी तुलना करें तो इसी अवधि में 561 घटनाएं ही सामने आई थीं। आंकड़े बताते हैं कि इस साल 270 घटनाएं अकेले तरनतारन में और 144 घटनाएं अमृतसर के इलाके में सामने आई हैं। जो बताती हैं कि इन दोनों इलाकों में विशेष रूप से ध्यान देने और पराली जलाने से रोकने के लिये ठोस कदम उठाने की जरूरत है। उल्लेखनीय है कि पंजाब में अभी भी धान की फसल काटने का मौसम चल रहा है। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि इस साल पराली प्रबंधन के लिये 576 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इसके अलावा सख्सिडी वाली लगभग 21,155 मशीनें उपलब्ध कराई गई थीं। दरअसल, सरकारी आर्थिक मदद के बावजूद किसानों को मशीनों को चलाने के खर्च, धान की कटाई और गेहूँ की बुवाई के बीच बहुत कम समय समय मिलने और जरूरत के समय मशीनें न मिल पाने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उल्लेखनीय है कि वैज्ञानिक तरीके से पराली प्रबंधन करने में प्रति एकड़ दो हजार से लेकर ढाई हजार रुपये तक खर्च आ सकता है। तभी आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे किसानों को पराली जलाना सबसे आसान विकल्प लगता है। हालांकि, शासन व प्रशासन ने पराली जलाने से रोकने के लिये सख्खी बढ़ा दी है। सूत्रों के अनुसार अब तक पराली जलाने के मामले में 113 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। इसके अलावा जमीन के रिकॉर्ड में 205 रेड एंट्री की गई हैं। साथ ही 11.4 लाख रुपये का पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का आर्थिक दंड लगाया गया है। निस्संदेह, देश में व्याप्त पर्यावरण संकट के मद्देनजर ऐसी कार्रवाई करना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि खेतों में पराली जलाने से समाज को प्रदूषण के रूप में सेहत के लिये भारी कीमत चुकानी पड़ती है। हालांकि, केवल जुर्माना लगाने से व्यावहारिक विकल्पों की कमी पूरी नहीं हो सकती। साथ ही, साफ हवा बनाये रखने की पूरी कीमत अकेले किसानों को ही नहीं चुकानी चाहिए।

डिजिटल उपस्थिति जैसी व्यवस्थाएं पारदर्शिता बढ़ाने में उपयोगी हो सकती हैं। उनसे यह पता लगाया जा सकता है कि शिक्षक और विद्यार्थी निर्धारित समय पर संस्थान पहुंच रहे हैं या नहीं। लेकिन तकनीक अपने आप शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं करती। उपस्थिति दर्ज हो जाने के बाद भी यह प्रश्न बना रहता है कि शिक्षक ने कितना पढ़ाया, विद्यार्थी ने कितना समझा और सीखने में पिछड़ रहे बच्चों की मदद कैसे की गई।

यदि प्रशासन का पूरा ध्यान हाजिरी दर्ज कराने पर केंद्रित हो जाए, तो शिक्षक की भूमिका पढ़ाने के बजाय आंकड़े पूरे करने तक सीमित होने का खतरा है। निगरानी का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि शिक्षण को बेहतर बनाना होना चाहिए। शिक्षक की जवाबदेही आवश्यक है, लेकिन उसके साथ पर्याप्त संसाधन, शैक्षणिक सहयोग और सम्मानजनक कार्य वातावरण भी जरूरी है।

बिहार की शिक्षा व्यवस्था की एक बड़ी चुनौती शिक्षकों पर गैर-शैक्षणिक कार्यों का बोझ भी है। चुनाव, विभिन्न सर्वेक्षणों, प्रशासनिक अभियानों और दूसरी जिम्मेदारियों के कारण कई बार शिक्षण प्रभावित होता है। सरकारी कामकाज में कुछ अतिरिक्त दायित्व जरूरी हो सकते हैं, लेकिन यदि वे नियमित रूप से कक्षा के समय को कम करने लगें, तो इसका सीधा नुकसान विद्यार्थियों को होता है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षकों का अधिकतम समय शिक्षण, पाठ-योजना, विद्यार्थियों की समस्याओं को समझने और मूल्यांकन में लगे।

शिक्षकों की कमी और विषय विशेषज्ञों की अनुपलब्धता भी कई संस्थानों में पढ़ाई को प्रभावित कर सकती है। कहीं विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में शिक्षक पर्याप्त नहीं हैं, तो कहीं विज्ञान, गणित और अन्य विषयों के अध्यापन में कठिनाइयां आती हैं। ऐसी परिस्थितियों में केवल उपस्थिति की जांच से समस्या हल नहीं होगी। नियुक्तियों, शिक्षकों के युक्तिसंगत पदस्थापन और विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता पर भी ध्यान देना होगा।

महाविद्यालयों की स्थिति पर भी गंभीर चर्चा जरूरी है। उच्च शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल डिग्री दिलाना नहीं, बल्कि उनमें स्वतंत्र चिंतन, विश्लेषण क्षमता, शोध की प्रवृत्ति और समाज को समझने की दृष्टि विकसित करना है। यदि महाविद्यालयों में नियमित कक्षाएं नहीं चलती, शिक्षक समय पर उपलब्ध नहीं होते या पाठ्यक्रम समय से पूरा नहीं होता, तो विद्यार्थियों की शैक्षणिक नींव कमजोर होती है। इसका प्रभाव आगे प्रतियोगी परीक्षाओं, रोजगार और उच्च शिक्षा के अवसरों पर पड़ता है।

# क्या वित्तमंत्री को शेयर बाजार की फ़िफ़्र है?

(लेखक- डॉ योगेन्द्र श्रीवास्तव)

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का यह बयान काबिलेगौर है कि वे कैपिटल गेन यानी पूंजीगत लाभ के बारे में सुझाव सुनने के लिये तैयार हैं। ज्ञात हो कि हर साल बजट के पहले वित्त मंत्रालय के पोर्टल पर कॉर्पोरेट, विशेषज्ञ और आम जनता से बजट सम्बन्धी सुझाव मॉंगे जाते हैं। इसके अलावा वित्त मंत्रालय में मीटिंग्स का दौर भी चलता है जिसमें आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के साथ बजट प्रस्तावों पर विमर्श होता है। ऐसी मीटिंग्स फिलहाल जारी हैं। गौरतलब है कि बहुत सी कम्पनियों के अच्छे तिमाही नतीजों और मुनाफे ने बढ़ोत्तरी के बावजूद शेयर बाजार लम्बी सुस्ती के दौर में हैं। विदेशी निवेशक बिकवाली करके पैसा वापस अपने देशों में निवेश कर रहे हैं जहाँ उन्हें बेहतर अवसर और ज्यादा फायदे की गुंजाइश है। सिर्फ अक्टूबर माह में विदेशी निवेशक 40 हजार करोड़ रुपये की बिकवाली कर चुके हैं जो कतई अच्छा संकेत नहीं है। यह सही है कि शेयर बाजार की सेहत का असर आम नागरिक के जमा खर्च पर नहीं पड़ता लेकिन विदेशी निवेश और मजबूत शेयर बाजार किसी भी देश की आर्थिक स्थिति और भावी प्रगति का पैमाना होता है। वर्ष 1992 में शेयर बाजार की भरी उठापटक पर तत्कालीन वित्तमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद में कहा था कि; मैं शेयर बाजार के लिये अपनी नींद खराब नहीं करता। लेकिन लगता है वर्तमान वित्तमंत्री महोदया की नींद खराब हुई है इसीलिए उन्होंने ऐसा उदार सुझाव दिया है और निवेशक बड़ी बेसब्री से सरकार के अगले कदम की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

ज्ञात हो कि पहले शेयर बेचने पर होने वाले लम्बी अवधि लाभ यानी एक साल से ज्यादा अवधि के बाद बेचने पर

महाविद्यालयों में कक्षाएं खाली रहने के पीछे केवल विद्यार्थियों की उदासीनता को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा। संस्थागत अनुशासन, शिक्षकों की उपलब्धता, पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता, पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं की स्थिति तथा रोजगार की संभावनाओं से जुड़ी चिंताएं भी विद्यार्थियों के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। इसलिए समस्या का समाधान एकतरफा कार्रवाई से नहीं, बल्कि संस्थानों की समग्र समीक्षा और सुधार से निकलेगा।

इस पूरी बहस में परीक्षा परिणामों की भूमिका को भी सही संदर्भ में समझना होगा। अच्छे अंक निश्चित रूप से विद्यार्थियों की मेहनत और उपलब्धि का संकेत हो सकते हैं। लेकिन परीक्षा में सफलता और वास्तविक सीखने के स्तर को एक ही चीज मान लेना उचित नहीं है। विद्यार्थी यदि पाठ को समझने, अपने शब्दों में उतर लिखने, गणितीय अवधारणाओं को लागू करने या किसी समस्या का तार्किक समाधान खोजने में कठिनाई महसूस करते हैं, तो परीक्षा परिणामों के साथ सीखने की गुणवत्ता की जांच भी आवश्यक है।

मूल्यांकन व्यवस्था का उद्देश्य केवल यह तय करना नहीं होना चाहिए कि कौन विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ और कौन असफल। उसे यह भी बताना चाहिए कि विद्यार्थी ने क्या सीखा, कहां कठिनाई हुई और आगे किस प्रकार की सहायता की जरूरत है। इसके लिए नियमित कक्षा-आधारित मूल्यांकन, विषयवार दक्षताओं की जांच और कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त शिक्षण की व्यवस्था जरूरी है। इससे परीक्षा परिणामों को वास्तविक शैक्षणिक सुधार से जोड़ा जा सकेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी रटने पर आधारित पढ़ाई से आगे बढ़कर समझ, कौशल, आलोचनात्मक चिंतन और अनुभव आधारित सीखने पर जोर देती है। लेकिन नीति के उद्देश्यों को जमीन पर उतारने के लिए पर्याप्त शिक्षक, प्रशिक्षित शैक्षणिक नेतृत्व, उपयुक्त शिक्षण सामग्री और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप योजनाओं की आवश्यकता है। केवल नीति का उल्लेख करने या नई व्यवस्था लागू करने से बदलाव नहीं आएगा; उसके प्रभाव का नियमित मूल्यांकन भी होना चाहिए।

बिहार जैसे राज्य में शिक्षा का सवाल सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास से भी जुड़ा है। गरीब परिवारों, ग्रामीण क्षेत्रों और वंचित समुदायों के बच्चों के लिए सरकारी विद्यालय और महाविद्यालय आगे बढ़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। यदि इन संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलेगी, तो संपन्न परिवार निजी संस्थानों का सहारा ले सकेंगे, जबकि कमजोर

कैपिटल गेन पर पूरी टैक्स छूट थी। लेकिन 1 अप्रैल 2018

से इसे 10 प्रतिशत और बाद में 2024 से बढ़ा कर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया। दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार ने शेयर पर मिलने वाले लाभोंश को भी नहीं छोड़ा और 2020 से उस पर भी टैक्स लगा दिया गया जबकि पहले लाभोंश पर कम्पनी टैक्स देती थी और इन्वेस्टर को प्राप्त होने वाला लाभोंश पूर्णतः कर मुक्त था। लाभोंश पर टैक्स वास्तव में टैक्स पर टैक्स है क्योंकि कम्पनियां पहले ही कई तरह के टैक्स दे चुकी होती हैं जिनमें मुनाफे पर टैक्स भी शामिल होता है।

पहले शेयर बाजार केवल रईस लोगों का शौक समझा जाता था मगर अब स्थितियां बदल चुकी हैं। पिछले 10 सालों में निवेशकों की संख्या में 10 गुना बढ़ोत्तरी हुई है। वर्ष 2015 में देश में डीमेट खातों की संख्या लगभग 2.5 करोड़ थी जो 2026 तक 25 करोड़ से अधिक हो चुकी है। नौकरीपेशा लोग आम तौर पर फिक्स डिपॉजिट में निवेश किया करते थे लेकिन लगातार घटती ब्याज दरों के कारण लोग निवेश के दूसरे रास्ते अपनाने पर मजबूर हैं ताकि बढ़ती हुई महंगाई और मुद्रास्फीति का मुकाबला कर सकें। निवेशकों की तादाद में वृद्धि का एक कारण यह भी है कि शेयर बाजार का कारोबार पूरी तरह ऑनलाइन और डिजिटल होने से निवेश बहुत सुविधाजनक हो गया है और घर बैठे मोबाइल के जरिये सारे लेनदेन करना भी बिल्कुल आसान है। इसीलिए अब नौकरीपेशा और रिटायर होने वाले नागरिक केवल फिक्स डिपॉजिट में निवेश पर भरोसा नहीं करते हैं बल्कि शेयर बाजार और म्यूचुअल फण्ड में भी निवेश करते हैं। इसलिए कैपिटल गेन पर टैक्स का असर उस मध्यम वर्ग पर पड़ता है जो कम होती ब्याज दर से बेहतर रिटर्न की

आर्थिक स्थिति वाले विद्यार्थियों के अवसर सीमित हो जाएंगे। इस प्रकार शिक्षा की गुणवत्ता में असमानता सामाजिक और आर्थिक विषमता को और गहरा कर सकती है।

सरकार को शिक्षा सुधार के लिए कुछ स्पष्ट कदम उठाने चाहिए। पहला, विद्यालयों और महाविद्यालयों में कक्षाओं के नियमित संचालन की निगरानी हो तथा उसके निष्कर्ष सार्वजनिक किए जाएं। दूसरा, डिजिटल उपस्थिति के आंकड़ों का उपयोग वास्तविक शिक्षण की समीक्षा के साथ किया जाए। तीसरा, शिक्षकों को अनावश्यक गैर-शैक्षणिक दायित्वों से मुक्त कर पढ़ाने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। चौथा, विषयवार शिक्षक-रिक्तियों, आधारभूत सुविधाओं और विद्यार्थियों के सीखने के स्तर की नियमित समीक्षा हो। पांचवां, निरीक्षण व्यवस्था दंडात्मक कार्रवाई तक सीमित न रहे, बल्कि शिक्षकों और संस्थानों को शैक्षणिक सहायता भी उपलब्ध कराए।

इसके साथ अभिभावकों और स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ाना भी जरूरी है। विद्यालय शिक्षा समितियां और महाविद्यालयों के प्रबंधन निकाय केवल औपचारिक संस्थाएं बनकर न रह जाएं। उन्हें कक्षाओं के संचालन, विद्यार्थियों की उपस्थिति, पुस्तकालय और प्रयोगशाला की स्थिति तथा स्थानीय शैक्षणिक जरूरतों पर चर्चा करने का वास्तविक अवसर मिलना चाहिए। शिकायतों के समाधान की पारदर्शी व्यवस्था हो, ताकि समस्याओं को समय रहते पहचाना जा सके।

शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षकों को केवल संदेह की नजर से देखना भी उचित नहीं है। बड़ी संख्या में शिक्षक सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। व्यवस्था की कमियों का बोझ केवल उन पर डालने से समाधान नहीं निकलेगा। जरूरी है कि जवाबदेही और सहयोग साथ-साथ चलें। जो लापरवाही या अनियमितता के दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई हो; वहीं अच्छा काम करने वाले शिक्षकों और संस्थानों को प्रोत्साहन मिले।

बिहार की शिक्षा व्यवस्था को अब आंकड़ों की सफलता से आगे बढ़कर सीखने की वास्तविक सफलता पर ध्यान देना होगा। खाली कक्षाएं, उपस्थिति में संभावित अनियमितताएं और अव्वल परीक्षा परिणाम अपने-आप में विरोधाभास नहीं हैं, लेकिन इनके बीच का संबंध जांच और समीक्षा की मांग करता है। सवाल यह नहीं कि कितने विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए, बल्कि यह भी है कि वे जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए कितना ज्ञान और कौशल हासिल कर पाए।

# प्रयश्चित ही कर्म फल से मुक्ति का आधार है

यह ठीक है कि जिस व्यक्ति के साथ अनाचार बरता गया अब उस घटना को बिना हुई नहीं बनाया जा सकता। सम्भव है कि वह व्यक्ति अन्यत्र चला गया हो। ऐसी दशा में उसी आहत व्यक्ति की उसी रूप में क्षति पूर्ति करना सम्भव नहीं। किन्तु दूसरा मार्ग खुला है। हर व्यक्ति समाज का अंग है। व्यक्ति को पहुँचाई गई क्षति वस्तुतः प्रकारान्तर से समाज की ही क्षति है। उस व्यक्ति को हमने दुःकर्मों से जितनी क्षति पहुँचाई है उसकी पूर्ति तभी होगी जब हम उतने ही वजन के सत्कर्म करके समाज को लाभ पहुँचाये। समाज को इस प्रकार हानि और लाभ का बैलेन्स जब बराबर हो जायेगा तभी यह कहा जायेगा कि पाप का प्रायश्चित हो गया और आत्मग्लानि एवं आत्मप्रताड़ना से छुटकारा पाने की स्थिति बन गई।

सस्ते मूल्य के कर्मकाण्ड करके पापों के फल से छुटकारा पा सकना सर्वथा असम्भव है। स्वाध्याय, सत्संग, कथा, कीर्तन, तीर्थ, व्रत आदि से चित्त में शुद्धता की वृद्धि होना और भविष्य में पाप वृत्तियों पर अंकुश लगाने की बात समझ में आती है। धर्म कृत्यों से पाप नाश के जो माहात्म्य शापाङ्क में बताये गये हैं उनका तात्पर्य इतना ही है कि मनोभूमि का शोधन होने से भविष्य में बन सकने वाले पापों की सम्भावना का नाश हो जाये। ईश्वरीय कठोर न्याय व्यवस्था में ऐसा ही विधान है कि पाप परिणामों की आग में जल मरने से जिन्हें बचना हो वे समाज की उत्कृष्टता बढ़ाने की सेवा-साधना में संलग्न हों और लदे हुए भार से छुटकारा प्राप्त कर शान्ति एवं पवित्रता की स्थिति उपलब्ध कर लें।

# सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सड़कों पर होगा महासंग्राम!

**विचारमंथन**

(लेखक – सनत जैन )

भारतीय राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संघर्ष कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब यह लड़ाई राजनीतिक दल, संसद और संवैधानिक संस्थाओं के साथ-साथ सड़कों पर आकर लड़ने लगें, तो स्थिति की गंभीरता को समझना जरूरी हो जाता है। 1 नवंबर को दिल्ली में प्रस्तावित विपक्ष की रैती ने इसी सवाल को केंद्र में ला दिया है। लोकतंत्र में असहमति का मुकाबला संवाद से होगा, या शक्ति प्रदर्शन से होगा? कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ महारैली की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस और विपक्षी दलों की ओर से इसमें 10 लाख लोगों को जुटाने की घोषणा की गई है। इसी

बीच 30 अक्टूबर को सड़क पर संसद आयोजित कर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेश करने की विपक्ष की घोषणा ने राजनीतिक टकराव को नया आयाम दे दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव की संवैधानिक प्रक्रिया और उसके लिए निर्धारित कानूनी आधार को समझना भी जरूरी है। दिल्ली पुलिस की अनुमति को लेकर उठे विवाद ने भी राजनीतिक बहस को और भी तेज कर दिया है। विपक्ष की प्रमुख मांगों में मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग शामिल है। विपक्ष का आरोप है, मतदाता सूची में बदलाव नागरिकों के मताधिकार को समाप्त कर रहा है। इसके विपरीत, भाजपा

विपक्ष के आंदोलन को चुनौती देते हुए नवंबर में ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ के नारे के साथ देशव्यापी पदयात्राओं और प्रदर्शनों की तैयारी कर रही है। राजनीतिक संघर्ष में अब तक विपक्ष सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरता था, अब उसमें सत्ता पक्ष भी सार्वजनिक प्रदर्शन के माध्यम से जवाब देने की तैयारी में है। इससे दोनों पक्षों में टकराव बढ़ता चला जा रहा है। आगे चलकर गृह युद्ध जैसी संभावनाओं को भी बनाता हुआ दिख रहा है। इस टकराव के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए बयान मोदी क्या मोदी का बाप भी इस्तीफा देगा, इस पर भी विवाद खड़ा हुआ है। खड़गे के बयान पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उनसे माफी की मांग की है। इस घटनाक्रम ने मताधिकार और

चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मूल मुद्दों के साथ राजनीतिक भाषा और नेताओं की सार्वजनिक जिम्मेदारी को भी बहस का हिस्सा बना दिया है।

लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही सड़कों पर आकर आंदोलन कर रहे हैं। यह स्थिति पहली बार देश में देखने को मिल रही है। जब सरकार और विपक्ष दोनों ही सड़कों पर हों, एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए हर स्थिति में जाने को तैयार हों। इसमें सबसे ज्यादा परेशानी कानून व्यवस्था को लेकर हो रही है। यदि सत्ता पक्ष को प्रदर्शन और रैली की अनुमति दी जाती है, तो विपक्ष भी मुकाबले में आकर अपने आंदोलन और प्रदर्शन तेज करेगा। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तकलीफ यह है, सीमित संसाधन होते हुए जिस तरह से दिल्ली सहित

*लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही सड़कों पर आकर आंदोलन कर रहे हैं। यह स्थिति पहली बार देश में देखने को मिल रही है। जब सरकार और विपक्ष दोनों ही सड़कों पर हों, एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए हर स्थिति में जाने को तैयार हों। इसमें सबसे ज्यादा परेशानी कानून व्यवस्था को लेकर हो रही है। यदि सत्ता पक्ष को प्रदर्शन और रैली की अनुमति दी जाती है, तो विपक्ष भी मुकाबले में आकर अपने आंदोलन और प्रदर्शन तेज करेगा।*

अन्य राज्यों में बड़ी संख्या में प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके पास इतना बल नहीं है, जो इतनी बड़ी संख्या में हो रहे प्रदर्शनों को व्यवस्थित कर पाए। जिस तरह की स्थिति बनने लगी है, उसको लेकर सबसे बड़ी चिंता कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन की बढ़ती चली जा रही है। प्रशासन दो पाटों के बीच में एक तरह फंस गया है। जिस तरह की स्थितियां देश में बन रही हैं, वह अच्छी नहीं कहीं जा सकती हैं।

सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में संवाद होना जरूरी है। जिस तरह से लोकसभा के मानसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में संवाद नहीं हुआ। अभी मानसून सत्र स्थगित भी नहीं हुआ है। आगे भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में संवाद की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है, जिसके कारण चिंता बढ़ती जा रही है। सरकार को गंभीरता से इस स्थिति पर विचार करना चाहिए।





## संक्षिप्त

## समाचार

### परदेसमें भारतीय महिलाओं का सहारा बनी लेडीज कॉर्नर, सुशीला शर्मा हक की अगुवाई



बर्लिन, एजेंसी। परदेस में अकेलेपन का दर्द समझने वाली चार भारतीय महिलाओं ने 40 साल पहले जो एक संस्था बनाई थी, उसका पूरा सफर अब एक किताब में दर्ज हो चुका है। मुंबई से बर्लिन पहुंची सुशीला शर्मा हक की अगुवाई में लेडीज कॉर्नर बर्लिन ने चार दशक पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर संस्था की सदस्य कविता पाल ने विशेष स्मारिका 40 ग्लोरियस ईयर्स ऑफ लेडीज कॉर्नर बर्लिन तैयार की और इसे केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को खुद भेंट किया। स्मारिका जर्मनी में भारत के राजदूत अजित गुप्ते को भी सौंपी गई। सुशीला शर्मा हक ने भारत में टाटा इंस्टीट्यूट से समाजसेवा की पढ़ाई की थी। बर्लिन पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां भारतीय समुदाय की गतिविधियां भारत मजलिस के इर्द-गिर्द सिमटी थीं, जिसे यूरोप की पहली भारतीय संस्था माना जाता है। वहां ज्यादातर पुरुष ही जुटते थे और महिलाओं को केवल तीज त्योहारों पर बुलाया जाता था। सुशीला ने उन पुरुषों की पत्नियों और महिला मित्रों से एक-एक कर संपर्क साधा। 1985 में सुशीला ने सुधा कोठारी, डोरा सेमूएल और छाया सेनगुप्ता के साथ मिलकर लेडीज कॉर्नर की नींव रखी। यहां अब वे धार्मिक उत्सव, मनोरंजन से लेकर रोजमर्रा की परेशानियों पर खुलकर चर्चा कर सकती हैं। संस्था का दायरा बढ़ता गया। भारतीय महिलाओं को हर तरह की मदद दी गई और विदेश में भाषा, संस्कृति, त्योहार व सरकार जीवित रखे गए। सुशीला कहती हैं कि चार दशक पूरे कर चुकी संस्था लेडीज कॉर्नर जर्मनी की एक अंतरराष्ट्रीय संस्था का हिस्सा है। कविता पाल ने स्मारिका में इन चार दशक की यादें, तस्वीरें, प्रेरक कहानियां और उपलब्धियां पिरोई हैं। वह कहती हैं, यह स्मारिका आने वाली पीढ़ियों के लिए एक धरोहर है।

### सेना का दावा- 218 लड़ाके और कमांडर मारे गए, अब तक 78 सैन्य वाहन भी तबाह

अदन, एजेंसी। यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ सेना ने बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई करने का दावा किया है। यमन के सशस्त्र बलों के सैन्य प्रवक्ता



माजिद अब्दुल्ला अल-नुजैली के मुताबिक, 'डॉन ऑफ यमन' अभियान के तहत पिछले 24 घंटे में 753 सटीक हमले किए गए। इन हमलों में करीब 218 हूती लड़ाकों और मैदानी कमांडरों को मार गिराने का दावा किया गया है। सैन्य प्रवक्ता ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अभियान की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सेना ने हूती विद्रोहियों के सैन्य ठिकानों, आपूर्ति मार्गों और उनके कमांड नेटवर्क को निशाना बनाया। इन कार्रवाइयों का उद्देश्य विद्रोहियों की सैन्य गतिविधियों और दोबारा संगठित होने की क्षमता को कमजोर करना था। अल-नुजैली ने बताया कि हमलों में मैदानी कमांड और नियंत्रण केंद्रों, सैन्य ठिकानों, किलेबंदी, हथियारबंद समूहों और विद्रोहियों की मदद के लिए भेजे जा रहे अतिरिक्त बलों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा, उनके परिवहन और आपूर्ति के साधनों पर भी कार्रवाई की गई। सेना के प्रवक्ता के अनुसार, इन हमलों से हूती विद्रोहियों की आवाजाही और युद्ध के मोर्चों तक सैन्य संसाधन पहुंचाने की क्षमता प्रभावित हुई। इससे सरकारी बलों को अलग-अलग मोर्चों पर आगे बढ़ने और अभियान चलाने में मदद मिली। यमन की सेना ने अभियान में हूती विद्रोहियों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है।

## ब्राजील में लूला की वापसी: बोल्सोनारो ने हार मानने से किया इनकार, चुनावी नतीजे रद्द करने की उठाई मांग

ब्रासीलिया, एजेंसी।

ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव में लुइज इनासियो लूला डा सिल्व्वा ने अपने प्रतिद्वंद्वी फ्लावियो बोल्सोनारो को हराकर जीत हासिल की। इस जीत के साथ देश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिला। चुनाव में हार के बाद बोल्सोनारो ने नतीजों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और चुनाव रद्द करने की मांग उठाई। लूला की जीत को लैटिन अमेरिका की राजनीति के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे क्षेत्र में वामपंथी विचारधारा वाले नेताओं की स्थिति मजबूत हुई है। करीब 44 लाख वोटों

मिली जीत

ब्राजील के चुनाव अधिकारियों के मुताबिक, सभी वोटों की गिनती पूरी होने के बाद लूला को कुल 51.8 फीसदी वोट मिले। उन्होंने बोल्सोनारो को करीब 44 लाख वोटों से पीछे छोड़ दिया। नतीजों की घोषणा के बाद लूला के समर्थकों में जश्न का माहौल बन गया। साओ पाउलो में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए, जबकि रियो डी जनेरियो में गाड़ियों के हॉर्न बजाकर जीत का जश्न मनाया गया। ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने के बाद लुइज इनासियो लूला डा सिल्व्वा ने कहा कि उनकी पार्टी ने



लोगों को यह समझाने में सफलता हासिल की कि ब्राजील ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए मतदान करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि उनकी जीत के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए किए गए विदेशी हस्तक्षेप को भी मात मिली है। लूला ने साफ कहा कि

ब्राजील किसी दूसरे देश का पिछवाड़ा नहीं है और देश अपने फैसले खुद लेने में सक्षम है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी सरकार देश चलाने के तरीके में बदलाव करेगी और फैसले लेने की प्रक्रिया में आम लोगों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी, ताकि जनता की आवाज को अधिक महत्व मिल सके। चुनाव में हार के बाद बोल्सोनारो ने मतदान का समय बढ़ाने के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने इसे असाधारण कदम बताते हुए नतीजों को रद्द करने की मांग की। हालांकि, मतदान का समय बढ़ाने की मांग दोनों उम्मीदवारों की ओर से की गई थी। लूला के समर्थकों ने कुछ

शहरों में बसों से मतदान केंद्रों तक पहुंचने में परेशानी की शिकायत की थी, जबकि बोल्सोनारो के समर्थक इलाकों में भारी बारिश के कारण दिक्कतें सामने आई थीं। मतदान खत्म होने से कुछ मिनट पहले ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस क्रिस्टियानो जैनिन ने मतदान का समय दो घंटे बढ़ाने का आदेश दिया। इस फैसले से कई मतदान केंद्रों पर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। कुछ जगहों पर वोटिंग मशीनें बंद हो चुकी थीं, जबकि कई केंद्रों पर चुनावी प्रक्रिया को लेकर भ्रम बना रहा। इसके चलते मतगणना में भी देरी हुई। बोल्सोनारो के सहयोगियों ने

फैसले पर सवाल उठाए और जस्टिस के पुराने राजनीतिक संबंधों का जिक्र किया। इस चुनाव में महंगाई, रोजगार और अपराध जैसे मुद्दों का खास असर देखने को मिला। बोल्सोनारो ने अपराध पर सख्ती बरतने और रोजमर्रा की चीजों की कीमतें कम करने का वादा किया था। दूसरी ओर, लूला ने सामाजिक कल्याण योजनाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा को अपने प्रचार का अहम हिस्सा बनाया। पहले दौर में पिछड़ने के बाद लूला ने अपने अभियान को बदलाव किया और युवाओं समेत अलग-अलग वर्गों के मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश की।

## ब्राजील में राष्ट्रपति चुनाव: अमेरिका और ट्रंप के विरोधी लूला की जीत, दूसरे दौर के मतदान के बाद आए नतीजे

रियो डी जनेरियो, एजेंसी। ब्राजील में रविवार को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर के लिए मतदान



के बाद नतीजे आ चुके हैं। इसमें मौजूदा राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्व्वा को बहुमत मिला है। जेल में बंद पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के बेटे फ्लावियो बोल्सोनारो के साथ कड़े मुकाबले के बीच लूला ने जीत दर्ज की। दोनों उम्मीदवारों को जनवरी में देश का अगला राष्ट्रपति बनने के लिए 50 प्रतिशत से अधिक वोट हासिल करने थे। लूला 50 फीसदी से अधिक वोट हासिल करने में सफल रहे। ब्राजील चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि लैटिन अमेरिका में अमेरिका का बढ़ता प्रभाव और मजबूत होगा या वामपंथी नेतृत्व मजबूत रहेगा। मतदान और नतीजों से पहले आए सर्वेक्षणों में दोनों उम्मीदवारों के बीच काटे की टक्कर दिखाई गई थी। वामपंथी विचारधारा

सुर्खियों में रहे हैं। चुनाव में प्रतिद्वंद्वी फ्लावियो बोल्सोनारो अमेरिका की तरफ झुकाव रखने के साथ ट्रंप के सहयोगी भी रहे हैं। फ्लावियो, जेल में बंद ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के बेटे हैं। इस महीने की शुरुआत में हुए चुनाव के पहले चरण में फ्लावियो ने लूला से 22 लाख से अधिक वोट हासिल किए थे। हालांकि, करीब 16 करोड़ मतदाताओं वाले देश में 3.30 करोड़ से अधिक लोगों ने मतदान नहीं किया था, जबकि ब्राजील में मतदान करना अनिवार्य है। अमेरिका के साथ संबंधों, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक कल्याण जैसे मुद्दों पर लूला और फ्लावियो के विचार एक-दूसरे से काफी अलग हैं। फ्लावियो की जीत से लैटिन अमेरिका के सबसे अधिक

## छात्रों ने पलटी बाजी: वुसिक की सत्ता खत्म, राष्ट्रपति ने खुद मानी हार; 2017 में संभाली थी कमान



मिल सकती हैं। वहीं, वुसिक की सर्बियन प्रोग्रेसिव पार्टी की 104 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया। बाकी सीटें जातीय अल्पसंख्यकों की पार्टियों के खाते में जा सकती हैं। अगर ये अनुमान अंतिम नतीजों में बदलते हैं, तो सर्बिया की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है। चुनाव के शुरुआती नतीजे सामने आते ही बेलग्रेड में छात्रों और उनके समर्थकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। छात्र आंदोलन के मुख्यालय में लोग 'जीत, जीत' के नारे लगाते दिखे। कहीं तालियां बज रही थीं, तो कहीं लोग एक-दूसरे को गले लगाकर खुशी जाहिर कर रहे थे। बेलग्रेड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रादोमिर साइचिक ने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि आज लोगों की आवाज

छात्र आंदोलन पिछले दो साल से वुसिक सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा था। आंदोलन ने युवाओं के साथ समाज के दूसरे वर्गों का भी ध्यान खींचा। सरकार के कामकाज और वुसिक की बढ़ती सत्तावादी शैली को लेकर असंतोष इस चुनाव का अहम मुद्दा बना। वुसिक एक दशक से ज्यादा समय तक सर्बिया की राजनीति में प्रभावशाली बने रहे। पिछले महीने छात्रों के बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने राष्ट्रपति पद छोड़ने और समय से पहले चुनाव कराने का फैसला किया था। अब शुरुआती नतीजे उनके राजनीतिक भविष्य के लिए बड़ा झटका माने जा रहे हैं।

### यूरोप की राजनीति पर भी पड़ सकता है असर

वुसिक की हार के संकेतों ने यूरोप में लोकतंत्र और सत्ता परिवर्तन को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। उनके करीबी सहयोगी माने जाने वाले हंगरी के नेता विक्टर ओर्बन की राजनीतिक मुश्किलों से भी इस घटनाक्रम की तुलना की जा रही है। हालांकि, सर्बिया में सत्ता परिवर्तन की पूरी तस्वीर अंतिम चुनाव परिणामों और आगे बन्नने वाली सरकार पर निर्भर करेगी। फिलहाल इतना साफ है कि छात्रों के आंदोलन ने देश की राजनीति में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है।

## 50 साल बाद विदेश में सेना भेजेगा अल्जीरिया

### नाइजर में तेल और गैस ठिकानों की सुरक्षा पर नजर, क्या है मामला



के लिए नहीं भेजा जा रहा, बल्कि उसे अहम आर्थिक ढांचे की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाएगी। उनके मुताबिक, साहेल क्षेत्र में बदलते हालात को देखते हुए अल्जीरिया को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ रहा है। नाइजर में अल्जीरिया की दिलचस्पी की एक बड़ी वजह प्राकृतिक गैस से जुड़ी परियोजना भी है। अल्जीरिया की सरकारी ऊर्जा कंपनी सोनाट्राच

नाइजर के साथ मिलकर ट्रांस-सहारा गैस पाइपलाइन परियोजना पर काम कर रही है। इस परियोजना के तहत नाइजीरिया से प्राकृतिक गैस को नाइजर के रास्ते अल्जीरिया तक लाने की योजना है। इसके बाद गैस को यूरोपीय देशों के बाजारों में पहुंचाया जा सकेगा। ऐसे में इस परियोजना से जुड़े बुनियादी ढांचे की सुरक्षा दोनों देशों के लिए काफी अहम है।

अफ्रीका के पश्चिमी साहेल इलाके में लंबे समय से हिंसा और अस्थिरता बनी हुई है। नाइजर, माली और बुर्किना फासो जैसे देश अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट से जुड़े हथियारबंद गुटों के हमलों का सामना कर रहे हैं। इन संघटनों के हमलों में बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं। इसके अलावा, पिछले कुछ वर्षों में इन तीनों देशों में सैन्य तुच्छापलट भी हुए हैं। राजनीतिक उथल-पुथल और लगातार हो रहे हमलों के कारण यहां की सुरक्षा व्यवस्था पर भारी दबाव है। अल्जीरिया का यह फैसला नाइजर के साथ उसके सुरक्षित रिश्तों का भी संकेत देता है। अगस्त में नाइजर की सैन्य सरकार के खिलाफ बग़ावत की कोशिश हुई थी। जनरल अब्दौराहमाने त्चियानी के नेतृत्व वाली सत्ता के समर्थन में अल्जीरिया खुलकर सामने आया था।

## 'खत्म की ईरान की परमाणु क्षमता': ट्रंप का दावा, कहा- होर्मुज से बढ़ी तेल सप्लाई



तरह तबाह कर दिया है। आप जानते हैं, यह नुकसान किसी की भी कल्पना से कहीं ज्यादा था। वह खत्म हो चुकी है।' वैश्विक ऊर्जा बाजार में उतार-चढ़ाव की आशंकाओं के बीच ट्रंप ने दावा किया कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य से अधिक तेल का परिवहन हो रहा है। उन्होंने इसका श्रेय अमेरिकी नौसेना

की नाकेबंदी और सैन्य अभियानों को दिया। ट्रंप ने कहा, 'मुझे पता था कि इससे कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। अब अगर आप देखें, तो कल वॉल स्ट्रीट जर्नल के पहले पन्ने पर था कि होर्मुज जलडमरूमध्य से निकलने वाला तेल अब युद्ध से पहले के स्तर से भी आगे निकल गया है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि हमने नाकेबंदी की है और हमारी सेना, खासकर हमारी नौसेना ने शानदार काम किया है।' उन्होंने आगे कहा, 'हमने समुद्री नाकेबंदी कर रखी है और इस समय होर्मुज से युद्ध शुरू होने से पहले के मुकाबले ज्यादा तेल निकल रहा है।' इस बीच, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराबची ने कहा कि भविष्य में युद्ध होता है या नहीं, इससे ईरान की नीतियों पर असर नहीं पड़ेगा। ईरानी समाचार एजेंसी आर्सेएनए के मुताबिक, उन्होंने चेतावनी दी कि

तेहरान के खिलाफ दोबारा सैन्य कार्रवाई करना तर्कहीन होगा। अराबची ने कहा, 'आज फिर युद्ध की बातें हो रही हैं, लेकिन अब से मैं युद्ध के बारे में सोच रहा हूं। युद्ध हो या न हो, हमारी नीतियां अपनी जगह बनी रहेंगी।' सऊदी अरब में मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद अमेरिका ने अपने गैर-आपातकालीन सरकारी कर्मचारियों और उनके पात्र परिवार के सदस्यों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास ने इसकी जानकारी दी। अमेरिकी विदेश विभाग ने यह फैसला नारिक हवाई अड्डों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों से पैदा हुए सुरक्षा जोखिमों को देखते हुए लिया है। रिफाइनरियों और सऊदी अरब के कई अन्य विमानन तथा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया।

## 'बीबी को वोट दें': इसाइल चुनाव से पहले ट्रंप का नेतन्याहू को समर्थन



चॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसाइल में होने वाले चुनाव से पहले एक बार फिर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने इसाइल के नागरिकों से नेतन्याहू को वोट देने की अपील करते हुए उन्हें एक बेहतरीन और साहसी प्रधानमंत्री बताया। ट्रंप ने दोनों नेताओं के करीबी संबंधों और ईरान के खिलाफ संयुक्त सैन्य अभियान का भी जिक्र किया।

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर सोशल पर एक पोस्ट में नेतन्याहू की तारीफ की। उन्होंने अमेरिकी सैन्य अभियानों का हवाला देते हुए दावा किया कि ईरान की सैन्य ताकत और अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचा है। ट्रंप ने लिखा, 'इसाइल के लोगों से, खासकर उन लोगों से जिन्होंने इसे नहीं देखा है, मैं एक सप्ताह पहले आपके प्रधानमंत्री बीबी नेतन्याहू के समर्थन में दिए गए अपने बयान को साझा कर रहा हूं। जैसा कि सभी जानते हैं, यहां तक कि दुश्मन भी जानते हैं कि बीबी और मेरे बीच अच्छे संबंध रहे हैं और हमने मिलकर जीत हासिल की है।' उन्होंने लिखा, 'मैंने वेनेजुएला में हमला किया, जो इतिहास के सबसे सफल सैन्य अभियानों में से एक था। लेकिन

उससे पहले हमने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया, जिससे दुनिया के आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले सबसे बड़े देश को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका गया। इसके बाद हमने ऑपरेशन एफिक फ्यूरी चलाया। अब ईरान के पास न नौसेना है और न वायुसेना। उसकी सेना और अर्थव्यवस्था दोनों बुरी हालत में हैं। ईरान में महंगाई दर भी 301 प्रतिशत है।' ट्रंप ने ईरान की नौसैनिक नाकेबंदी का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि इस नाकेबंदी के कारण ईरान को तेल नहीं मिल पा रहा है और उसके सैन्य तथा अन्य नेतृत्व के दो स्तर खत्म हो चुके हैं। उन्होंने कहा, 'जब आप मतदान करने जाएं, तो याद रखें कि बीबी एक बेहतरीन और साहसी प्रधानमंत्री रहे हैं। कुछ बेहद बुरे लोगों ने इसाइल के लोगों से अभियान को पूरा करने की अपील करते हुए कहा, 'दुनिया भर में अब 'अमेरिका की मौत हो, इसाइल की मौत हो' जैसे नारे नहीं सुनाई देने चाहिए और ऐसा नहीं होगा। प्रधानमंत्री के लिए बीबी नेतन्याहू को वोट दें। हमें उस काम को पूरा करना है, जिसकी शुरुआत हमने की थी।'

## दिलजीत के शो, स्कूलों और पंजाब विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

चंडीगढ़, एजेंसी। चंडीगढ़ और मोहाली में बम धमाके की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। धमकी भरे ईमेल और संदेशों में कई स्कूलों, पंजाब विधानसभा और पंजाबी गायक व अभिनेता दिलजीत दोसांझ के आगामी शो को निशाना बनाने की बात कही है। मामले की गंभीरता को देखकर संबंधित एजेंसियां संदेशों की सत्यता और उनके स्रोत का पता लगाने में जुटी हैं। जानकारी के अनुसार, वायरल हो रहे धमकी भरे संदेशों में चंडीगढ़ के सेक्टर-42 स्थित एसआर किड्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल और सेक्टर-44 के सेंट जेवियर स्कूल के अलावा मोहाली के कुछ स्कूलों का उल्लेख है। इसके साथ ही पंजाब विधानसभा परिसर को निशाना बनाने की धमकी दिए जाने का दावा है। वायरल ईमेल के स्क्रीनशॉट में अवटूर से 27 नवंबर तक अलग-अलग स्थानों पर धमाके करने की चेतावनी होने की बात कही गई है। हालांकि, इन संदेशों में किए गए दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मामले में दिलजीत दोसांझ के आगामी म्यूजिकल शो का जिक्र होने से चिंता बढ़ गई है। संदेशों में कार्यक्रम को निशाना बनाने की धमकी देने का दावा किया गया है। सुरक्षा एजेंसियां संभावित खतरों को ध्यान में रखकर मामले की जांच में जुटी हैं। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि धमकी भरे संदेश किसने भेजा और उनका उद्देश्य क्या है।

## मायावती की कांग्रेस को नसीहत : व्यक्तिगत हमले और जहरीली राजनीति देशहित में नहीं



लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम मायावती ने भारतीय राजनीति में व्याप्त कटुता और व्यक्तिगत हमलों पर गहरी चिंता जाहिर की है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए, विशेषकर कांग्रेस को परोक्ष रूप से नसीहत देकर कहा कि ऐसी विषैली और अमर्यादित राजनीति देश के लिए उचित नहीं है। बसपा प्रमुख मायावती ने लिखा कि आज भारतीय राजनीति में आपसी अविश्वास, द्वेष और आरोप-प्रत्यारोप का स्तर व्यक्तिगत हमलों तक पहुंच चुका है। उन्होंने इस व्यवहार को असंसदीय, अमर्यादित, अपमानजनक, संकीर्ण और कभी-कभी हिंसक बयानबाजी तक पहुंचने वाला बताया, जो अत्यंत दुःखद और देश की गरिमा व मान-मर्यादा के लिए चिंताजनक है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि यदि शीर्ष पदों पर बैठे लोगों के बीच आपसी सम्मान का अभाव है, तब भी आपत्तिजनक और विषैली राजनीति को किसी भी प्रकार से बढ़ावा नहीं देना चाहिए। उनके मुताबिक, इस तरह की बढ़ती स्वार्थी और संकीर्ण राजनीति से लोगों का भरोसा राजनीतिक व्यवस्था पर कमजोर हो रहा है, जो देश और जनहित के लिए शुभ संकेत नहीं है। मायावती ने देश में बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई जैसी ज्वलंत समस्याओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जनता पहले से ही इन मुद्दों से बेचैन है, और इसके बाद नेताओं के बीच की नाक की आपसी लड़ाई स्थिति को और विषम बना रही है। जनता चाहती है कि सभी का ध्यान इन गंभीर समस्याओं के समाधान पर केन्द्रित हो। उन्होंने सभी पार्टियों और उनके नेताओं से अशोभनीय टीका-टिप्पणी व बयानबाजी की होड़ से बचने की अपील की। मायावती ने आग्रह किया कि यह प्रवृत्ति राजनीतिक माहौल को और अधिक कड़वा व विषैला बनाएगी, जो पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने इस दिशा में सभी से समुचित ध्यान देने का आह्वान किया।

## सीएम फडणवीस का ऐलान: महाराष्ट्र के 1.5 करोड़ किसानों को मिलेगी 5,000 रुपये की सूखा राहत

मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र में सूखे जैसे हालात और फसलों को हुए नुकसान के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने करीब 1.5 करोड़ किसानों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। राज्य सरकार पात्र किसानों को अग्रिम सूखा राहत के रूप में 5,000 रुपये प्रति किसान देगी। इसके लिए कुल 7,500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राहत राशि के वितरण में बैंक किसी तरह की कटौती न करें और किसानों को पूरी रकम मिले। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला तब लिया गया है, जब राज्य के कई हिस्सों में किसान सूखे और आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। वर्षा में सीएम फडणवीस ने कहा कि 5,000 रुपये की सहायता से किसानों के पूरे नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन संकट के समय उन्हें तत्काल आर्थिक मदद जरूर मिलेगी। उन्होंने राज्य में किसानों को दी जाने वाली अग्रिम सहायता की महत्वपूर्ण पहल बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले कम जमीन वाले किसानों को कई बार केवल 1,000 रुपये तक की सहायता मिलती थी, जबकि अब पात्र किसानों को कम से कम 5,000 रुपये दिए



जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अग्रिम राहत है और किसानों को बाकी मुआवजा बाद में मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि बैंक किसानों की सहायता राशि से किसी प्रकार की कटौती न करें।

सीएम फडणवीस ने विपक्ष की आलोचनाओं का जवाब देकर कहा कि जिस तरह महिलाओं के लिए लाडकी बहिन योजना के तहत 1,500 रुपये की सहायता को लेकर सवाल उठाए थे, उसी तरह किसानों को दी जा रही राशि पर भी आलोचना की जा रही है। उन्होंने कहा कि

जरूरत के समय मिलने वाली छोटी आर्थिक मदद भी जरूरतमंद परिवारों के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसके पहले मुख्यमंत्री ने बताया था कि राज्य में सूखे की स्थिति घोषित किए गए तात्काल की संख्या 265 से बढ़ाकर 305 कर दी गई है। महायुति सरकार का कहना है कि फसल नुकसान और आर्थिक तंगी से जूझ रहे किसानों को राहत पहुंचाने के लिए इस बार सहायता प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। अब किसानों को राहत राशि मिलने और आगे के सुआवजों की प्रक्रिया पर नजर रहेगी।

## जम्मू-कश्मीर: उमर अब्दुल्ला मंत्रिमंडल में चार नए मंत्रियों ने ली शपथ, अधिकतम संख्या हुई नौ



अहमद वानी उर्फ अलताफ कालू शामिल हैं। उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी के साथ-साथ सकीना इट्टू, जावेद राणा और जावेद अहमद डार अपने मंत्री पदों पर बरकरार हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार, मंत्रिमंडल में यह फेरबदल बेहतर शासन और लोगों की शिकायतों के त्वरित अनंतनाग के पहलगाम से अलताफ

किया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ल ने पार्टी अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ल के परामर्श से वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया है। शपथ ग्रहण समारोह श्रीनगर शहर के चश्मा शाही इलाके में स्थित लोक भवन ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री उमर, एनसी अध्यक्ष डॉ. फारूक

अब्दुल्ल, अन्य मंत्री, वरिष्ठ नेता, सिविल और पुलिस अधिकारी सहित कई प्रमुख नागरिक उपस्थित थे। अब जम्मू-कश्मीर सरकार में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ल सहित कुल नौ मंत्री हैं सकीना इट्टू, जावेद डार, जावेद राणा, अली सागर, शमीमा फिरदौस, अलताफ कालू, मीर सैफुल्लाह और सुरिंदर चौधरी।

## हमीरपुर में एलाइड हेल्थकेयर कॉलेज शुरू, सीएम सुक्खू ने किया उद्घाटन... विद्यार्थियों से किया संवाद

शिमला, एजेंसी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द सिंह सुक्खू ने हमीरपुर के जोलसम्पड़ स्थित डॉ. आरकेजीएमसी एवं अस्पताल परिसर में एलाइड एवं हेल्थकेयर कॉलेज का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मेडिकल विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी पढ़ाई और प्रशिक्षण से जुड़े पहलुओं पर चर्चा की। कॉलेज के शुरू होने से प्रदेश के युवाओं को चिकित्सा क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा हासिल करने के एक मौके मिलने वाले हैं। अब तक रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, प्रयोगशाला तकनीक और डायलिसिस जैसे विषयों की पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों को मुख्य रूप से इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज पर निर्भर रहना पड़ता था। हमीरपुर में नया संस्थान शुरू होने से विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र में ही प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। अटल आ्युर्विज्ञान एवं अनुसंधान



विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2026-27 के प्रवेश संबंधी विवरण के अनुसार, कॉलेज में शुरूआती चरण में चार स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए कुल 210 सीटें निर्धारित की गई हैं। इसमें बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस और बैचलर ऑफ एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर

टेक्नोलॉजी में 60-60 सीटें हैं। वहीं, बैचलर ऑफ डायलिसिस थैरेपी टेक्नोलॉजी में 30 सीटें उपलब्ध होंगी। विद्यार्थियों को सैद्धांतिक शिक्षा के साथ अस्पतालों में जांच, चिकित्सा उपकरणों के संचालन और मरीजों के उपचार में सहयोग से संबंधित व्यावहारिक प्रशिक्षण मिलेगा। कॉलेज के संचालन के लिए आवश्यक मशीनरी और

उपकरण खरीदने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 6.87 करोड़ रुपये जारी करने का निर्णय लिया है। हिमाचल सरकार ने भविष्य में छह पाठ्यक्रमों के माध्यम से कुल 330 सीटें उपलब्ध कराने की योजना भी घोषित की है। इसमें प्रयोगशाला विज्ञान, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, ऑटोमेट्री और फिजियोथेरेपी में 60-60 सीटें तथा डायलिसिस तकनीशियन पाठ्यक्रम में 30 सीटें प्रस्तावित हैं। इसके अलावा, शैक्षणिक सत्र 2026-27 से आईजीएमसी शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज में बैचलर ऑफ रेडिएशन थैरेपी टेक्नोलॉजी शुरू करने का निर्णय लिया गया है। दोनों संस्थानों में 30-30 सीटें होंगी। स्टेट एलाइड एवं हेल्थकेयर कार्डसिल के चेयरमैन विनोद चौहान ने सरकारी क्षेत्र में देश का पहला एलाइड हेल्थकेयर कॉलेज बताकर अन्य पाठ्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

### टाइगर श्रॉफ पर हमले का खुलासा, बिश्नोई गैंग ने दहशत फैलाने रची थी साजिश

मुंबई, एजेंसी। बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुए जानलेवा हमले की गूथी को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सुलझा लेने का दावा किया है। पुलिस जांच में यह आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है कि इस हमले के पीछे किसी व्यक्तिगत दुश्मनी का मामला नहीं, बल्कि कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ था। क्राइम ब्रांच के मुताबिक बिश्नोई गैंग ने फिल्म उद्योग में अपना वर्चस्व स्थापित करने, भारी रकम की रंगदारी वसूलने और समाज तथा सेलिब्रिटीज के बीच दहशत का माहौल पैदा करने के सोचे-समझे मकसद से इस वारदात को अंजाम दिया था। यह हमला एक संगठित अंतरराज्यीय आपराधिक गिरोह द्वारा अवैध और घातक हथियारों की मदद से पूरी योजना बनाकर किया गया था। यह सनसनीखेज घटना 18 अक्टूबर की शाम को मुंबई के पॉश इलाके जुहू में घटी थी। टाइगर श्रॉफ अपनी कार से एक फुटबॉल ग्राउंड के परिसर से बाहर निकल रहे थे, तभी हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर कई राउंड गोलियां चला दीं। इस गोलीबारी में टाइगर श्रॉफ बाल-बाल बच गए, हालांकि कार के कांच टूटने से उनके हाथ और छाती पर हल्की खरोंचे आई थीं। इस हमले में टाइगर का ड्राइवर और पास में खड़ा एक अन्य ऑटो वाला गोली लगने से घायल हो गए थे, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया था। घटना के बाद मुंबई पुलिस ने विभिन्न राज्यों की पुलिस टीमों और विशेष जांच इकाइयों के साथ मिलकर एक व्यापक तलाश अभियान शुरू किया। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने एक बंद अंतरराज्यीय नेटवर्क का पर्दाफाश किया और अब तक कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

## 200 सीटें मांग रही कांग्रेस पर आप का तंज... फिर सपा को 1000 सीटें मिलनी चाहिए

### पिछले चुनाव में कांग्रेस को महज ढाई प्रतिशत वोट और सिर्फ दो सीटें मिलीं

सिर्फ दो सीटें मिली थीं। इस आधार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, अगर दो सीटों के आधार पर आप 200 सीटें मांग रहे हैं, तब 111 सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी को 1000 सीटें मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में, यूपी में नया परिसीमन कराना पड़ेगा और जब विधानसभा में डेढ़-दो हजार सीटें होंगी, तब जाकर 1000 सीट पर सपा और 200 पर कांग्रेस लड़ पाएगी। संजय सिंह

ने नेताओं को ऐसी बात नहीं करने की नसीहत दी जो व्यावहारिक ना लगे।

आप सांसद ने कांग्रेस को अपराधबोध से बाहर निकलने की सलाह देकर उसकी कार्यप्रणाली पर कई राज्यों के चुनावी नतीजों का जिक्र किया। उन्होंने हरिशणा का उदाहरण देकर कहा कि आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन की चर्चा कई दौर तक चली, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने फोन उठाना बंद कर दिया

और आप को अपने दम पर लड़ना पड़ा। उन्होंने मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव को नजरअंदाज करने, महाराष्ट्र में लोकसभा जीत के बाद खींचतान के कारण बाजी पलटने और बंगाल में ममता बनर्जी, दिल्ली में केजरीवाल तथा बिहार में तेजस्वी को मुख्यमंत्री चेहरा स्वीकार करने में देरी जैसी गलतियों को पूरे विपक्ष के लिए नुकसानदेह बताया।

भाजपा और संघ पर निशाना साधकर संजय

### कर्नाटक में एसआईआर के बाद 1.08 करोड़ मतदाताओं के नाम कटे, अंतिम मतदाता सूची जारी

बेंगलुरु, एजेंसी। कर्नाटक में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी की गई है। जारी आंकड़ों के मुताबिक, करीब 1.08 करोड़ मतदाताओं के नाम अंतिम सूची में शामिल नहीं किए हैं। इसमें बड़ी संख्या इसतरह के लोगों की है, जिन्होंने एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं किया था। यह संख्या राज्य के कुल मतदाताओं का करीब 19.48 प्रतिशत है। वहीं, चुनाव आयोग की जांच और सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 61,867 लोगों को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए अयोग्य पाया गया है। अंतिम सूची में कुल 4.46 करोड़ मतदाताओं को शामिल किया गया है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए अनुपस्थित, स्थायी रूप से स्थानांतरित, मृत और डुबोकेट मतदाताओं की पहचान की। आंकड़ों के अनुसार, 65,45,679 मतदाता यानी 11.81 प्रतिशत स्थायी रूप से स्थानांतरित मिले।

## थेनी जेलब्रेक के बाद स्टालिन का हमला, तमिलनाडु में कानून-व्यवस्था पूरी तरह फेल

चेन्नई, एजेंसी। तमिलनाडु के थेनी जिले की जेल से 17 कैदियों के फरार होने की घटना ने राज्य का कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। डीएमके प्रमुख और पूर्व सीएम एमके स्टालिन ने विजय के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार पर निशाना साधकर सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर खामियों का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य में हालात इसतरह के हैं कि लोगों को अपनी सुरक्षा खुद करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पूर्व सीएम स्टालिन ने व्यांग्यत्मक पोस्ट के जरिए थलापति सरकार को

आलोचना की। उन्होंने 'ब्रेकिंग बैड' और 'प्रिजन ब्रेक' जैसी टीवी सीरीज का जिक्र कर कहा कि तमिलनाडु में अब जेल से कैदियों के भागने की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार अपराधियों पर निगरानी रखने में नाकाम है, तब जेल के अंदर बंद कैदी भी आसानी से कैसे फरार हो रहे हैं।

डीएमके प्रमुख ने चेन्नई की पुज़ल सेंट्रल जेल से



पुलिस के अनुसार, थेनी की जिला जेल से अलग-अलग मामलों में सजा काट रहे 17 कैदी फरार हुए। घटना के बाद पुलिस ने व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया। अधिकारियों ने बताया कि फरार कैदियों में से एक को जेल के पास से ही पकड़ लिया गया। अन्य कैदियों की तलाश जारी है। इस घटना ने जेलों की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।